

आवश्यकता

### ३. आत्मनिर्भर भारत की ओर.....

मिका होती

नए सिरे से

न स्वस्थ

प्रा. डॉ. वैशाली खेडकर

सहायक अध्यापक (हिंदी विभाग), रयत शिक्षण संस्था का, महात्मा फुले महाविद्यालय, पिंपरी-१७.

उनके लिए

है तो इसकी

आत्म निर्भर

भीर रहेंगे।

भारत प्राचीन काल से ही संसाधनों से परिपूर्ण देश रहा है। क्योंकि पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। जिसके आधार पर जीवन उपयोगी वस्तुओं से लेकर राष्ट्र निर्माण तक की कई वस्तुएं बिना किसी की मदद से बना सकते हैं। अर्थात् भारत कहीं हद तक आत्मनिर्भर देश है और अधिक आत्मनिर्भर बनने की भी जरूरत है।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था। लेकिन भुखमरी और गरीबी के कारण इसमें बहुत सी बाधाएं उत्पन्न हुईं। 1 साल से हम कोरोना जैसी भयानक वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं। संपूर्ण व्यापार जगत बंद पड़ा है।

छोटे कुटीर उद्योग पतियों से लेकर बड़े से बड़े पूंजीपतियों तक हो भारी नुकसान हुआ है। खास तौर पर निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों की कमाने-खाने की समस्या काफी बढ़ गई है। सभी देशों के बीच सामानों का आदान-प्रदान बंद है। इसलिए लॉकडाउन के दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनने का आवाहन किया। उन्होंने लोकल फॉर वोकल का भी नारा दिया - इसका अर्थ है लोकल वस्तुओं का उपयोग और प्रचार करना तथा उनकी पहचान बनाना।

आत्मनिर्भर का अर्थ है किसी और पर अवलंबित न रहना। प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है कि वह आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार के साथ - साथ राष्ट्र के उत्थान में भी अपना योगदान दें।

बहुत से लोग लघु एवं मध्यम उद्योगों द्वारा वस्तुएं बनाकर और गुणवत्ता धारक वस्तुओं को अन्य जगहों पर बेचकर व्यापार भी बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती, मत्स्य पालन, आंगनवाड़ी तथा महिला बचत समूह की ओर से बनाई गई सामग्री आदि उद्योग आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद है। इस प्रकार यह उद्योग अपने परिवार से गांव गांव से जिला एक दूसरे से जोड़कर देखें तो पूरे राष्ट्र को योगदान देते हैं।

आत्मनिर्भर भारत योजना का सूत्रपात 12 मई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत एवं गतिशील करने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं। भारत अभियान सबसे ज्यादा जोर स्वयं रोजगार पर दिया गया है। इसके तहत अनेक प्रकार के लोन एवं सब्सिडी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत (MSME) लोन, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), शिशु मुद्रा लोन, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (CLSS) आदि लोन और सब्सिडी तथा अन्य प्रकार की योजनाएं भी शामिल हैं। भारत योजना में सबसे ज्यादा ध्यान इंटरेंट (इरादा), इंकलूजन (समावेशन), इन्वेस्टमेंट

